



131

P- 2244- I-16

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार -

श्री शुक्ल सिंह उर्फ सुकल सिंह बरकड़े पिता स्व. श्री बसोरी उर्फ बसोरा गौड़ निवासी ग्राम सरौरा पोस्ट पड़वार तहसील व जिला जबलपुर।

विरुद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
2. श्री कृष्ण कुमार साहू पिता बेडीलाल साहू
उम्र 39 साल निवासी ग्राम परतला पोस्ट पड़वार
तहसील व जिला जबलपुर।

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1- मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 24/अ-21/2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दि. 06/06/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री शुक्ल सिंह उर्फ सुकल सिंह बरकड़े पिता स्व. श्री बसोरी उर्फ बसोरा गौड़ निवासी ग्राम सरौरा पोस्ट पड़वार तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम देवरीकला प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 98, 99 रकबा क्रमशः 0.760, 0.310 हे. कुल रकबा 1.070 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री कृष्ण कुमार साहू पिता बेडीलाल साहू उम्र 39 साल निवासी ग्राम परतला पोस्ट पड़वार जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02/01/2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3- प्रकरण में तहसीलदार बरगी द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ-21/15-16 में प्रतिवेदन दि. 28/04/2016 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत 4.88 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात्

// 1 //

शुक्ल सिंह

P
16

श्री धारा-3 चयन
किस आज दि. 5/7/16 को
प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

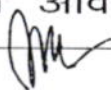
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण 2247/एक/2016

जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.7.16	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 24/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम देवरीकला, प.ह.न. 21 रा.नि.म. इमलई, तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 98, 99 रकवा क्रमशः 0.760, 0.310 है0 कुल रकवा 1.070 हैक्टेयर भूमि अनावेदक क्रमांक 2 कृष्ण कुमार साहू पुत्र श्री बेड़ीलाल साहू, निवासी ग्राम परतला, पोस्ट पड़वार, जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इसलिये आवेदक को भूमि विक्रय करने</p>	

R
2/16



की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 24/अ-21/2015-16 पंजीबद्ध कर आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर से करायी। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आदेश दिनांक 06.06.2016 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि भूमि के मूल्य की गणना वर्ष 2015-16 गाईडलाईन के अनुसार की गयी है, जबकि वर्तमान में गाईडलाईन वर्ष 2016-17 प्रचलित है। इसलिए मूल्य की गणना का स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये है। ऐसी स्थिति में आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन विचार होने से रह गया है। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने दिनांक 06.06.2016 को आवेदन पत्र पर

R
/g

M

सद्भाविक विचार नहीं किया और प्रकरण में निर्देश दिये हैं कि भूमि की मूल्य की गणना वर्ष 2015-16 की गाईडलाईन के आधार पर की गयी है, जबकि वर्तमान में गाईडलाईन वर्ष 2016-17 प्रचलित है। इस संबंध में बताया गया कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 02.01.2016 को प्रस्तुत किया है, ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में गाईडलाईन वर्ष 2015-16 की लागू होगी ना कि वर्ष 2016-17 की और फिर भी जब आदिवासी को भूमि की कीमत का भुगतान किया जायेगा तो वह वर्ष 2016-17 के गाईडलाईन के अनुसार ही होगा। ऐसी स्थिति में जो आदेश कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

5- म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा तर्कों में बताया गया कि उपरोक्त प्रकरण में कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6- उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद

R
2/2

M

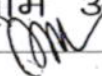
वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, इस कारण आदेश दिनांक 06.06.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी शेष कास्तकारी भूमि जोकि सरौंरा एवं ग्राम कुकडीखेड़ा में स्थित है उसे कृषि उपयोगी बनाना चाहता है, ऐसी स्थिति में कुछ भूमि का विक्रय करना चाहता है। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जाँच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 4.88 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार





आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है, जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि

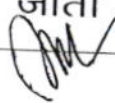
R/S

M


विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईडलाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर अनावेदक के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईडलाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है। जहाँ तक कलेक्टर न्यायालय का यह निष्कर्ष आवेदक द्वारा वर्ष 2015-16 के गाईडलाईन के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति चाही है, जबकि वर्तमान में गाईडलाईन वर्ष 1016-17 प्रचलित है। इस संबंध में कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में जिस वर्ष में गाईडलाईन के अनुसार भूमि की कीमत अधिक आती है उसी के अनुसार विक्रेता को भूमि का मूल्य दिलाया जाये।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रमांक 24/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को भूमि

B
JSC



ग्राम देवरीकला, प.ह.न.21 रा.नि.म. इमलई,
तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर में स्थित
भूमि खसरा नं. 98, 99 रकवा क्रमशः
0.760, 0.310 है० कुल रकवा 1.070
हैक्टेयर भूमि के विक्रय की अनुमति दी
जाती है।


सदस्य

R
/A